

खास खबरें

अब फेसबुक से भी कमाई कर पाएंगे लोग, विज्ञापनों के जरिए मिलेगा पैसा

कैलिफोर्निया। सोशल नेटवर्किंग मंच फेसबुक ने गुरुवार को कहा कि फेसबुक वीडियो बनाने वालों को विज्ञापनों के जरिए कमाई करने की सुविधा देगा। कंपनी ने कहा है कि वो प्लेटफॉर्म को मदद से ऐसे वीडियो बनाने वालों के लिए कमाई का नया रास्ता बनाने की योजनाओं का विस्तार करेगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि किन-किन तरीकों से लोग फेसबुक पर कमाई कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि फेसबुक पर वीडियो बनाने वाले लोग अब एक मिनट तक के वीडियो बनाकर पैसा कमा पाएंगे, जिसमें न्यूनतम रूप से 30 सेकंड का विज्ञापन चलेगा। तीन मिनट या उससे अधिक समय वाले वीडियो के लिए, 45 सेकंड का विज्ञापन दिखाया जाएगा। पहले केवल तीन मिनट या उससे अधिक समय के वीडियो पर लोग विज्ञापनों के साथ कमाई कर सकते थे, जिसमें कोई भी विज्ञापन 01 मिनट से पहले नहीं दिखाया जाता था।

कैसे मिलेंगे विज्ञापन : फेसबुक पर वीडियो में विज्ञापन पाने के लिए लोगों के वीडियोज को 6,00,000 मिनट देखा जाना जरूरी होगा, साथ ही संबंधित एकाउंट पर 05 या उससे अधिक सक्रिय वीडियो अपलोड होने जरूरी होंगे।

गूगल पे अब उपयोगकर्ताओं को देगा डाटा पर अधिक नियंत्रण



नई दिल्ली। गूगल ने बृहस्पतिवार को एलान किया कि वह गूगल पे के उपयोगकर्ताओं को उनके डाटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करेगी। कंपनी ने कहा, इसके लिये गोपनीयता के विस्तृत फीचर दिए जाएंगे जिससे लेनदेन के डाटा पर अधिक नियंत्रण की सुविधा होगी। इसके लिए अगले हफ्ते तक अपडेट जारी किया जाएगा। नए अपडेट के बाद उपयोगकर्ता यह तय कर सकते हैं कि उनकी लेन-देन गतिविधियों पर उन्हें कितना नियंत्रण रखना है। अपडेट करते ही पुछा जाएगा कि वे नियंत्रण को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ। गूगल पे के उपाध्यक्ष (उत्पाद) अमरीश केंडे ने कहा, गोपनीयता हमारे लिए पहले से ही एक प्रमुख प्राथमिकता है। यदि आप गूगल पे पर कुछ भी करते हैं, तो वह गूगल पे पर हो रहा है, यह आज की स्थिति है। अब हम गूगल पे पर भी आपकी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आपको नियंत्रण देने जा रहे हैं। गूगल पे पर मोबाइल रिचार्ज करने का उदाहरण देते हुए कहा, अब यूजर यह तय कर सकते हैं कि उन्हें ऑफर व रिबॉर्ड देने के लिए इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं।

कोरोना के बाद अमेरिका में पटरी पर लौटने लगा रोजगार बाजार

वाशिंगटन। अमेरिका में बेरोजगारी भते का लाभ उठाने वालों की संख्या पिछले सप्ताह घटकर 7,12,000 रह गई। यह संख्या पिछले साल नवंबर के बाद सबसे कम है। इससे यह पता चलता है कि इंग्लैंडर्स ने अब रोजगार में कटौती कम कर दी है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने और अर्थव्यवस्था में सुधार को इसकी वजह माना जा रहा है। श्रम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि बेरोजगारी सहायता के मामलों में एक सप्ताह पहले के 7,54,000 में से 42 हजार कम हो गए। रोजगार बाजार में हालांकि धीरे-धीरे मजबूती आ रही है लेकिन अभी भी कई व्यवसाय दबाव में चल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी भी 96 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण पिछले 12 माह से दबाव में है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में फरवरी माह के दौरान 3,79,000 रोजगार जोड़े गए। यह अक्टूबर माह के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में उभारोका अब अधिक खर्च कर रहे हैं और राज्यों तथा शहरों में कारोबारी प्रतिबंध अब हल्के हो रहे हैं। बहरहाल, बृहस्पतिवार को जारी बेरोजगारी के आंकड़े हालांकि पिछले चार माह के दौरान सबसे नीचे हैं लेकिन ये बताते हैं कि एतिहासिक तौर पर यह अब भी ऊंचे हैं। कोरोना वायरस महामारी फैलने से पहले यह आंकड़े काफी भी सात लाख तक नहीं पहुंचे थे। यहां तक कि बड़ी मंदी के समय भी इन्होंने सात लाख के आंकड़े को पार नहीं किया था।

स्पेशल खबर...

कच्चे तेल का आयात घटाना आसान नहीं...

पिछले तीन वर्षों में घरेलू क्रूड उत्पादन में 10 फीसदी की गिरावट

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल, 2020 के मुकाबले इस वर्ष मार्च में तीन गुना से भी ज्यादा हो गई हैं। ऐसे में आयातित क्रूड यानी कच्चे तेल पर निर्भरता को खत्म करने के प्रयासों को लेकर चर्चा जोरों पर है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार के इस लक्ष्य का भी जिक्र जरूरी है जिसमें उसने वर्ष 2022 तक आयातित तेल पर देश की निर्भरता 10 फीसद और वर्ष 2030 तक 50 फीसद घटाने की बात कही थी। हालांकि, आंकड़े ही बता रहे हैं कि जमीनी सच्चाई काफी अलग है। असल में पिछले तीन वर्षों में ही क्रूड के

घरेलू उत्पादन में 10 फीसद की गिरावट हुई है। इस अवधि में कच्चा तेल उत्पादन 3.56 करोड़ टन से घटकर 3.217 करोड़ टन रह गया है। वैसे, पेट्रोलियम मंत्रालय को भरोसा है कि अगले एक दशक में घरेलू स्तर पर क्रूड और प्राकृतिक गैस उत्पादन में अच्छी वृद्धि होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में क्रूड उत्पादन वर्ष 2011-12 में 3.81 करोड़ टन के साथ अपने उच्च स्तर पर रहा था। लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट का ही रुख बना हुआ है। इसके चलते आयातित क्रूड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड



एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014-15 में भारत ने 21.07 करोड़ टन (210 मिलियन मीट्रिक टन) क्रूड का आयात किया था जो वर्ष 2019-20 में बढ़ कर 27.007 करोड़ टन हो गया है। चालू

वित्त वर्ष के अप्रैल से जुलाई के आंकड़े बताते हैं कि 16.28 करोड़ टन क्रूड आयात किया गया है। इस तरह से वर्ष 2020-21 के दौरान संभावना है कि क्रूड आयात में कमी होगी। लेकिन यह घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी

अगले वर्ष से पहले इकोनॉमी का सामान्य होना मुश्किल : मूडीज

नई दिल्ली

अग्रणी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 के कारण कंपनियों और संस्थाओं की साख में जो गिरावट आई है, वह अल्पकालिक ही है। लेकिन आर्थिक गतिविधियों के मामले में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं वर्ष 2022 से पहले तक महामारी-पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंचेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले वर्ष 11 मार्च को ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। इसके बाद से पूरे वर्ष के दौरान महामारी ने दुनियाभर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में व्यवधान डाला है। इस वजह से ही कर्ज में गिरावट और भुगतान में चूक के मामले भी तेजी से बढ़े हैं और दुनियाभर की कई कंपनियों व संस्थाओं के समक्ष क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का संकट गहराया है।

कोरोना वायरस पर एक ग्लोबल रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न साख चुनौतियां काफी हद तक मौजूद हैं। हालांकि यह स्थिति लंबे अरसे



तक नहीं रहने वाली है और कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होना ही है। लेकिन उन क्षेत्रों के लिए जोखिम अधिक है, जिनकी सामान्य गतिविधियों पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं।

मूडीज ने कहा कि वर्ष 2022 तक अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं महामारी-पूर्व की गतिविधि के स्तर पर वापस नहीं आ पाएंगी। मूडीज ने कहा कि वह धीमी वैश्विक वापसी और व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण के आसपास अनिश्चितता सामान्य से बहुत अधिक रहने की उम्मीद करता है। रिपोर्ट में रेटिंग एजेंसी का कहना था कि

महामारी के नरम पड़ने के बाद सरकारों द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों से आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय बाजारों में सुधार दिखेगा। नीति निर्माता लंबे समय तक कई अन्य मामलों में कुछ वर्षों तक आर्थिक गतिविधियों को गति देने के अनुरूप नीतियां बनाते रहेंगे। मूडीज के मुताबिक टीकाकरण में तेजी को देखते हुए इस वर्ष महामारी की व्यापकता और संक्रमण संख्या घटेगी। इससे दुनियाभर की सरकारों को धीरे-धीरे लॉकडाउन पूरी तरह खत्म करने में मदद मिलेगी व आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आएगी।

पाकिस्तान ने एक बार फिर टिकटॉक पर लगाया बैन चीनी ऐप से फैल रही थी 'अश्लीलता'

नई दिल्ली

पाकिस्तान ने चीनी वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फैसला देश की मीडिया नियामक एजेंसी ने गुरुवार को लिया है। इससे पहले दो वकीलों ने अदालत का रुख कर दावा किया था कि इस ऐप के जरिए अश्लील सामग्री फैलाई जा रही है। करीब छह महीने पहले ही पाकिस्तानी नियामक एजेंसी ने 'टिकटॉक' को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उसे शिकायतें मिली थी कि सोशल मीडिया ऐप पर कथित अनैतिक व अश्लील सामग्री है। एजेंसी ने संक्षिप्त बयान में कहा कि उसने पेशावर उच्च न्यायालय के आदेश की तामील करते हुए 'टिकटॉक' को प्रतिबंधित किया है। इसके अलावा एजेंसी ने कोई और ब्यौर उपलब्ध नहीं कराया पेशावर उच्च न्यायालय ने कहा कि उसने वकील नाजिश मुजप्फर और सारा अली की

याचिका पर कार्रवाई की है। उन्होंने अपनी याचिका में गुजराशि की थी कि वीडियो साझा करने वाले ऐप को तब तक ब्लॉक रखा जाए जबतक वह पिछले साल पाकिस्तानी मीडिया नियामक द्वारा दिए गए निर्देशों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता।

पहले हटाया था बैन

महज तीन महीने पहले ही पाकिस्तान ने टिकटॉक से प्रतिबंध हटाया था। इसका संचालन करने वाली कंपनी की तरफ से 'अनैतिक सामग्री' को नियंत्रित करने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया था। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने अनैतिक सामग्री को शिकायतें प्राप्त होने के बाद नौ अक्टूबर को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रतिबंध हटाने के बाद अब एक बार फिर उसपर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

एक अप्रैल के बाद बढ़ सकते हैं टीवी सेट के दाम

नई दिल्ली

अगर आप नई टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर ध्यान से पढ़ें। इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि अगले महीने यानी अप्रैल से टीवी के दाम बढ़ जाएं। कई कंपनियां टीवी की कीमतों में इजाफा करने जा रही हैं। ऐसे में आपको अपनी प्लानिंग पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। दिग्गज टीवी कंपनी एलजी अपनी कीमत पहले ही बढ़ा चुकी है। पैनासोनिक, हायर व थॉमसन जैसी कंपनियों ने अप्रैल से दाम बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इनकी वृद्धि पांच से सात फीसद रहने का अनुमान है। हायर एप्लाइडस इंडिया के प्रेसिडेंट एरिक



ब्रिगेंजा का कहना था कि कंपनियों के पास दाम बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उल्लेखनीय है कि एलजी समेत कई कंपनियों ने तो पहले ही दाम बढ़ा दिए हैं। आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। असल में, चीन की कंपनियों की खेमेबंदी के चलते टेलीविजन सेट की कीमतों में आने वाले दिनों के दौरान बड़ी बढ़ोतरी निश्चित सी है। इस क्षेत्र की अधिकतर कंपनियों का कहना है कि ओपन-सेल पैल के दाम में बेतहाशा वृद्धि के

चलते अगले महीने से टीवी सेट की कीमत बढ़ानी होगी। पिछले एक महीने में पैल के दाम में 35 फीसद की हुई बढ़ोतरी से निर्माताओं पर काफी दबाव है। वैश्विक बाजार में ओपन-सेल पैल के मैन्यूफैक्चरिंग में चीनी कंपनियों का दबाव है। चीन की टेलीविजन कंपनियों इसका फायदा उठाते हुए कम कीमत के बूते टीवी सेट तैयार कर भारत जैसे उभरते बाजार में धाक जमाने की जुगत में है। उद्योग संस्था सीएमा व फोर्स्ट एंड सुविलन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में टीवी बाजार 2018-19 के 17.5 करोड़ यूनिट से तेजी से आगे बढ़ते हुए 2024-25 तक 28.4 करोड़ यूनिट का हो जाएगा।

अब 'ई-दुकान' से जुड़ेंगे गली के दुकानदार, देश में कहीं भी बेच पाएंगे सामान

नई दिल्ली। विदेशी ऑनलाइन कंपनियों से दो-दो हाथ करने के लिए अब देश के छोटे दुकानदार भी तैयार हैं। छोटे दुकानदारों के संगठन (कैट) ने एक ऐसा मोबाइल ऐप शुरू किया है जिससे हर दुकानदार जल्द शुरू होने वाले देसी ई-मार्केट पर मुफ्त में ई-दुकान खोल सकेगा।

खुलेगा मेड इन इंडिया ऑनलाइन बाजार : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) जल्द ही अपना खुद का ई-कॉमर्स पोर्टल 'भारत ई-मार्केट' खोलने जा रही है। कैट की योजना इस पोर्टल पर देश के सभी छोटे दुकानदारों को लाने की है। इस पर वेंडरों को ऑनबोर्ड लाने के लिए ही उसने ये मोबाइल ऐप शुरू की है। कैट हमेशा से फिलिपकाट और एमेजॉन जैसी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों की मुखर विरोधी रही है।

वॉरेन बफे ने 90 की उम्र में किया कमाल, 100 अरब डॉलर वलव में शामिल

नई दिल्ली

मशहूर निवेशक वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल रहे हैं। लेकिन हाल के सालों में टेक्नोलॉजीज शेरों में आई तेजी के चलते दौलत के मामले में दूसरे कई लोग बफे से काफी आगे निकल गए। लेकिन बफे ने फिर से टॉप अमीरों में वापसी की है। उनका नाम 100 अरब डॉलर की दौलत वाले अमीरों की फेहरिस्त में शामिल हो चुका है।

अब कितनी हुई दौलत : बुधवार को बफे की दौलत में 1.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिसकी वजह बर्कशायर क्लास ए शेरों का रिकॉर्ड हाई पर पहुंचना रहा। ब्लूमबर्ग बिलियेनियर इंडेक्स के मुताबिक, 90 बरस के हो चुके बफे की दौलत बुधवार को 100.4 अरब डॉलर पर पहुंच

गई। वह दुनिया के टॉप रईसों में इस वक छठें पायदान पर हैं। इस वक दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस हैं। उनके बाद एलन मस्क, बिल गेट्स, बर्नार्ड अरनॉल्ट, मार्क जुकरबर्ग हैं।

बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं बफे : वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं। इस कंपनी से उनकी काफी ज्यादा हिस्सेदारी है। कंपनी के शेयर इस साल 15 फीसदी चढ़े हैं, जबकि एस्पेंडपी 500 इंडेक्स ने 3.8 फीसदी तक की तेजी दिखाई है। बर्कशायर हैथवे के शेयरों में तेजी की एक वजह बफे द्वारा अपनी ही कंपनी के शेयरों के बाईबैक पर मोटा आमाउंट खर्च करने का कदम भी है। बीते साल 138 अरब डॉलर की नकदी रखने के चलते बफे की जमकर आलोचना हुई थी।

दान न की होती दौलत तो 192 अरब डॉलर के होते मालिक : बफे 2006 से अब तक 37 अरब डॉलर से ज्यादा के बर्कशायर स्टॉक दान कर चुके हैं। पहले बर्कशायर में उनकी करीब एक तिहाई हिस्सेदारी थी। बफे ने अपनी संपत्ति दान न की होती तो आज वह 192 अरब डॉलर के मालिक होते।

बफे गिविंग प्लेज नामक कंपनी के भी को-फाउंडर हैं। यह कंपनी परोपकार को प्रोत्साहित करता है। बफे ने 1965 में बर्कशायर हैथवे को खरीदा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 1.9 अरब डॉलर के राहत पैकेज का रास्ता साफ हो जाने के बाद इस हफ्ते शेयर बाजारों में काफी तेजी आई है। अमेरिका पहले भी 3 लाख करोड़ डॉलर का राहत पैकेज दे चुका है।

बजाज पल्सर एन 200 ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड, मात्र 23.68 सेकेंड्स में कर दिया ये कारनामा

नई दिल्ली

बजाज पल्सर एनएस 200 ने नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। ये रिकॉर्ड भारत में सबसे तेज क्वार्टर मील व्हीली के लिए है। जैसा की बजाज ऑटो का दावा है, सड़क परीक्षक ह्विपेश मंडके ने सैंडल पर इस रिकॉर्ड को बनाया। मोटर स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक सहायक की उपस्थिति में रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। बजाज पल्सर एनएस 200 ने 23.68 सेकंड में व्हीली को पूरा किया। हवाई अड्डे के रनवे पर व्हीली का प्रयास किया गया था जिसे रिकॉर्ड के लिए अवरुद्ध कर दिया गया था।



बजाज ऑटो का यह भी दावा है कि सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल देश के कुछ बेहतरीन और सबसे अनुभवी ऑटोमोबिल पत्रकारों और सड़क परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए थे।

स्टंट के लिए शोरूम स्टॉक का इस्तेमाल : जैसा कि बजाज ऑटो ने दावा किया है कि, विशेष रूप से बजाज पल्सर एनएस 200 मॉडल को इस्तेमाल किया गया था वह मूल शोरूम स्टॉक की स्थिति में था और नंबर प्लेट को हटाने के लिए स्टीवर्ड

रियल एस्टेट : इस साल 34 फीसदी घट सकती है मकानों की बिक्री

अगले वर्ष में सुधार की उम्मीद

नई दिल्ली

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि कोरोना महामारी के चलते चालू वित्त वर्ष 2020-21 में आवासीय इकाइयों की बिक्री में 34 फीसदी की गिरावट आ सकती है। हालांकि निम्न तुलनात्मक आधार के हिसाब से अप्रैल से शुरू हो रहे वर्ष 2021-22 में मांग में करीब इसी तेजी से वृद्धि भी दिख सकती है।

'के-शेप' की रिकवरी की उम्मीद : एजेंसी का अनुमान है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में अगले वित्त वर्ष में 'के-शेप' की रिकवरी आ सकता है। इसका अर्थ है कि बाजार नरमी से पूरी तरह से तो नहीं उबर सकेगा पर चालू वित्त वर्ष में गिरावट के बाद वृद्धि दर के आंकड़े अच्छे दिखेंगे।

2022 में बिक्री में 30 फीसदी की वृद्धि की उम्मीद : एजेंसी ने एक बयान में कहा कि, 'वित्त वर्ष 2021 में सालाना आधार पर 34 फीसदी की गिरावट के बाद वित्त वर्ष 2022 में बिक्री में 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जा सकती है।' हालांकि एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि वित्त वर्ष 2022 में समग्र बिक्री अभी भी वित्त वर्ष 2019-20 के स्तर से लगभग 14 फीसदी कम रह सकती है।



नौ महीने में बिक्री में 41 फीसदी की गिरावट

वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में कुल 32.6 करोड़ वर्गफीट आवासीय क्षेत्र की बिक्री हुई थी। एजेंसी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में सालाना आधार पर बिक्री में 41 फीसदी की गिरावट रही है। पूरे वित्त वर्ष में यह गिरावट 34 फीसदी रह सकती है। मालूम हो कि देश में रहने के लिहाज से बड़े शहरों में बंगलूरु और छोटे शहरों में शिमला सबसे बेहतर शहर है। भारत सरकारी की ओर 'ईज ऑफ लिविंग' (जीवन जीने की सुगमता) सूचकांक में यह जानकारी दी गई है। 'ईज ऑफ लिविंग' सूचकांक के तहत कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। इस सूची में पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है।